आकाशवाणी शिमला

10.11.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

मुख्य समाचार'

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के पड्डल मैदान में आपदा प्रभावितों को वितरित की 81 करोड़ रूपये से अधिक की राहत राशि– आपदा राहत पैकेज को बढ़ाकर 8 लाख रूपये करने की घोषणा।
- विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा–तपोवन में 26 नवम्बर से आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाकचौबंद।
- एबीवीपी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और नशे को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना।
- कुल्लू ज़िला के झनियार गांव में अग्निकांड की एक घटना में 16 मकान जलकर राख।
- आगामी सर्दियों के मौसम के दृष्टिगत शिमला ज़िला प्रशासन तैयारियों में जुटा।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से आपदा प्रभावित 4 हज़ार 9 सौ 14 लाभार्थियों को 81 करोड़ 28 लाख रूपये की राहत राशि वितरित की। इस अवसर पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए एक हज़ार 5 सौ 13 लाभार्थियों को चार–चार लाख रूपये की पहली किश्त प्रदान की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा राहत पैकेज को 7 लाख 70 हज़ार से बढ़ाकर 8 लाख रूपये करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र के पंगलूर में बाढ़ में अपने माता–पिता को खोने वाली बच्ची निकिता को भी 7 लाख 95 हज़ार रूपये का चैक प्रदान किया। उन्होंने निकिता के लिए 21 लाख रूपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों को वन अधिनियम के तहत वन भूमि पर एक बीघा जमीन दिलाने के लिए उन्होंने केन्द्र सरकार से मदद मांगी है जो कि अभी तक नहीं मिली है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मधु मांडव पहल का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

सुक्खू

इस बीच मुख्यमंत्री ने मंडी ज़िला के राजकीय महाविद्यालय पनारसा में 13 करोड़ 14 लाख रूपये की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

विधानसभा अध्यक्ष

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि धर्मशाला के तपोवन में 26 नवम्बर से आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। वे आज तपोवन विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा भवन के अंदर मोबाईल, लैपटॉप और अन्य इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं के ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान विधानसभा परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए

गए हैं। उन्होंने कहा कि 26 नवम्बर से 5 दिसंबर तक आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र में कुल 8 बैठकें होंगी।

रोहित ठाकुर

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर बुनियादी ढांचे और खेल सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने आज शिमला ज़िले के ठियोग उपमंडल के राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देहा के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय भवन बनाए जा रहे हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग में अब तक विभिन्न श्रेणियों के लगभग 7 हज़ार नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है और 9 हज़ार से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

एबीवीपी

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और नशे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। एबीवीपी की प्रांत मंत्री नेन्सी अटल ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है और कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। नेन्सी अटल ने बताया कि यदि प्रदेश सरकार शिक्षा व कानून व्यवस्था पर संज्ञान नहीं लेगी तो एबीवीपी प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करेगी। **——बाईट—नेन्सी अटल—**

आग

कुल्लू जिला में बंजार क्षेत्र के झनियार गांव में अग्निकांड की एक घटना में 16 मकान जलकर राख हो गए हैं। बंजार के एसडीएम पंकज शर्मा ने बताया कि अग्निकांड की सूचना मिलते ही राहत व पुनर्वास दल को तुरंत मौके पर रवाना किया गया। प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री और अंतरिम राहत राशि तत्काल उपलब्ध करवा दी गई है। घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं।

डीसी शिमला

आगामी सर्दियों के मौसम को देखते हुए शिमला ज़िला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आज शिमला में अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें बर्फबारी के दौरान यातायात, सुरक्षा और ज़रूरी सेवाओं को सुचारू रखने को लेकर रणनीति बनाई गई। उपायुक्त ने कहा कि शहर को पांच अलग—अलग सैक्टरों में बांटा गया है ताकि भारी बर्फबारी होने पर सड़कों को जल्द खोला जा सके और यातायात बाधित न रहे।

जीएसटी सुधार

केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर घटाने के बाद, 22 सितम्बर को शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव से देशभर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से स्टेशनरी क्षेत्र को मिलने वाले बढ़ावे पर। पेश है एक रिपोर्ट—

नई जीएसटी सुधारो के तहत सरकार ने स्टेशनरी उत्पादों पर महत्वपूर्ण राहत दी है। जिससे देशभर के छात्रों और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ है। पेंसिल, रबर, शार्पनर, क्रेन, नोटबुक, ग्राफ बुक और मानचित्र जैसी स्टेशनरी वस्तुओं पर कर की दर पहले के 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दी गई है। इसी प्रकार रबर पर जीएसटी की दरों को पहले के पांच प्रतिशत से घटाकर कर मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा ज्योमेट्री, बॉक्स, कलर बॉक्स और पाउच जैसी वस्तुओं पर जिन पर पहले 12 प्रतिशत कर लगता था अब 5 प्रतिशत जीएसटी कर दिया गया है।

इस क्षेत्र में घर में कटौती से छात्रों पर वित्तीय भोज काम हो रहा है और बाजार में इन पदों की खुदरा बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है। नए जीएसटी सुधार शिक्षा तक पहुंच कर किफायती बना रहे हैं। माध्यमिक विद्यालय में नामांकन को प्रोत्साहित कर रहे हैं और साथ ही घरेलू स्टेशनरी निर्माण की मांग को भी बढ़ावा दे रहे हैं।

प्रमाण पत्र

पैंशन व पैंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय एक से 30 नवम्बर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में 11 नवम्बर को ऊना और 12 को कांगड़ा में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर के दौरान पैंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग पर बल दिया जाएगा, जिससे पैंशन भोगियों को बॉयोमीट्रिक उपकरणों पर निर्भर नही होना पड़ेगा और वे स्मार्ट फोन के माध्यम से घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे।

मुख्य समाचार एक बार फिर''

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के पड्डल मैदान में आपदा प्रभावितों को वितरित की 81 करोड़ रूपये से अधिक की राहत राशि– आपदा राहत पैकेज को बढ़ाकर 8 लाख रूपये करने की घोषणा।
- विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा–तपोवन में 26 नवम्बर से आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाकचौबंद।
- एबीवीपी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और नशे को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना।
- कुल्लू ज़िला के झनियार गांव में अग्निकांड की एक घटना में 16 मकान जलकर राख।
- आगामी सर्दियों के मौसम के दृष्टिगत शिमला ज़िला प्रशासन तैयारियों में जुटा।